

## **GENERAL KNOWLEDGE – THE 15MIN SHOW**

### **योजनाएँ खबरों में (Schemes in News)**

1. How many traditional businesses have been included in the first phase of Pradhan Mantri Vishwakarma Yojana-2023?/प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना-2023 के पहले चरण में कितने पारंपरिक व्यवसायों को शामिल किया गया है?

- a) 16
- b) 17
- c) 18
- d) 19

- On August 15, from the ramparts of the Red Fort, PM Modi announced the launch of Vishwakarma Yojana.
- Now the cabinet has also approved Rs 13 thousand crore for the scheme. For the first time, families involved in 18 traditional occupations will be covered.
- This scheme will provide assistance to artisans and craftsmen in rural and urban areas across India. 'PM Vishwakarma Yojana' will be launched on Vishwakarma Jayanti on 17th September.
- 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से पीएम मोदी ने विश्वकर्मा योजना की शुरुआत करने का ऐलान किया। वहीं अब कैबिनेट ने योजना के लिए 13 हजार करोड़ रुपये भी मंजूर किए गए हैं।
- इसमें पहली बार 18 परंपरागत व्यवसायों से जुड़े परिवारों को कवर किया जाएगा। यह योजना पूरे भारत में ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के कारीगरों व शिल्पकारों को सहायता प्रदान करेगी।
- 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर 'पीएम विश्वकर्मा योजना' लॉन्च की जाएगी।

2. Vaibhav Fellowship 2023 is an initiative of which ministry of the Government of India?/वैभव फेलोशिप 2023 भारत सरकार के किस मंत्रालय की पहल है?

- a) Ministry of Education/शिक्षा मंत्रालय
- b) Ministry of Science and Technology/विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय
- c) Ministry of Women and Child Development/महिला एवं बाल विकास मंत्रालय
- d) All of above

- The Government of India has launched a new fellowship program called Global Indian Scientists (VAIBHAV) to facilitate collaboration between the Indian diaspora in Science, Technology, Engineering, Mathematics and Medicine (STEMM) and Indian educational and research institutions./भारत सरकार ने विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा (STEMM) तथा भारतीय शैक्षणिक एवं अनुसंधान संस्थानों में भारतीय डायस्पोरा के बीच सहयोग की सुविधा हेतु वैश्विक भारतीय वैज्ञानिक (VAIBHAV/वैभव) नामक एक नया फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया है।
- The main objective of Vaibhav Fellowship 2023 is to improve the ecosystem of Indian research institutes. For which the aim is to facilitate academic and research collaboration between Indian higher educational institutions and the best institutions of the world./वैभव फेलोशिप 2023 का मुख्य उद्देश्य भारतीय रिसर्च संस्थानों के पारिस्थितिकी तंत्र में सुधार करना है। जिसके लिए भारतीय उच्च शैक्षिक संस्थानों और दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों के बीच अकादमिक और अनुसंधान सहयोग की सुविधा प्रदान करना है।

## **GENERAL KNOWLEDGE – THE 15MIN SHOW**

### **योजनाएँ खबरों में (Schemes in News)**

- The program will focus on 18 identified knowledge verticals, including quantum technology, health, pharmaceuticals, electronics, agriculture, energy, computers and science./कार्यक्रम 18 पहचाने गए नॉलेज वर्टिकल्स पर ध्यान केंद्रित करेगा, जिनमें क्वांटम टेक्नोलॉजी, स्वास्थ्य, औषध क्षेत्र, इलेक्ट्रॉनिक्स, कृषि, ऊर्जा, कंप्यूटर और विज्ञान शामिल हैं।

3. Where was the Vibrant Village Program launched on 10 April 2023?/10 अप्रैल 2023 को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम कहाँ लांच किया गया था?

- a) Arunachal Pradesh/अरुणाचल प्रदेश
- b) Sikkim/सिक्किम
- c) Assam/असम
- d) Manipur/मणिपुर

- Recently, the Union Cabinet has approved the formation of seven new battalions of Indo-Tibetan Border Police (ITBP), as well as the Vibrant Villages Program to strengthen the social and security infrastructure on the China border. Programme- VVP) has allocated Rs 4,800 crore./हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत-तिब्बत सीमा पुलिस (Indo-Tibetan Border Police- ITBP) की सात नई बटालियनों के गठन को मंजूरी दी है, साथ ही चीन सीमा पर सामाजिक एवं सुरक्षा ढाँचे को मज़बूत करने हेतु वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम (Vibrant Villages Programme- VVP) के तहत 4,800 करोड़ रुपए आवंटित किये हैं।
- Its objective is to strengthen the security grid along the Line of Actual Control (LAC). It will also provide the ITBP an opportunity to rest, recuperate and train its personnel./इसका उद्देश्य वास्तविक नियंत्रण रेखा (Line of Actual Control- LAC) पर सुरक्षा ग्रिड को मज़बूत करना है। यह ITBP को अपने कर्मियों को आराम करने, स्वस्थ होने और प्रशिक्षित करने हेतु अवसर भी प्रदान करेगा।
- It is a centrally funded program announced in the Union Budget year 2022-23 (till 2025-26) with the goal of developing border villages in the North and improving the quality of life of the residents of such border villages./यह एक केंद्रीय वित्तपोषित कार्यक्रम है जिसकी घोषणा केंद्रीय बजट वर्ष 2022-23 (2025-26 तक) में उत्तर में सीमावर्ती गाँवों को विकसित करने और ऐसे This will include the border areas of Himachal Pradesh, Uttarakhand, Arunachal Pradesh, Sikkim and Ladakh./सीमावर्ती गाँवों के निवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लक्ष्य के साथ की गई।
- इसमें हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और लद्दाख के सीमावर्ती क्षेत्र शामिल होंगे।

4. National Hydrogen Mission 2023 India Target has been set to achieve net zero emissions by the year?/राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन 2023 भारत किस वर्ष तक शुद्ध शून्य उत्सर्जन हाशिल करने का लक्ष्य रखा है?

- a) 2050
- b) 2060
- c) 2070

## GENERAL KNOWLEDGE – THE 15MIN SHOW

### योजनाएँ खबरों में (Schemes in News)

d) 2080

- The Central Government has approved the National Green Hydrogen Mission, costing Rs 19,744 crore, which aims to make India a 'global hub' for the use, production and export of green hydrogen./केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन, जिसकी लागत 19,744 करोड़ रुपए है, को मंजूरी दी है इसका उद्देश्य भारत को हरित हाइड्रोजन के उपयोग, उत्पादन और निर्यात के लिये 'वैश्विक केंद्र' बनाना है।
- To develop a renewable energy capacity of about 125 GW (GigaWatt) in India by the year 2030 along with a green hydrogen production capacity of at least 5 MMT (Million Metric Tonnes) per annum./वर्ष 2030 तक भारत में लगभग 125 GW (गीगावाट) की नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता विकसित करने के साथ-साथ प्रतिवर्ष कम-से-कम 5 MMT (मिलियन मीट्रिक टन) की हरित हाइड्रोजन उत्पादन क्षमता का विकास करना।

5. India has started the first international power project to supply electricity to which country?/भारत ने पहली अन्तरराष्ट्रीय बिजली परियोजना की शुरुआत किस देश में बिजली आपूर्ति के लिए शुरू की है?

- a) Bhutan/भूटान
- b) Nepal/नेपाल
- c) Bangladesh/बांग्लादेश
- d) Sri Lanka/श्रीलंका

- This transnational power project of Adani Group will supply 1496 MW electricity to Bangladesh. This power will be supplied through a 400 KV dedicated transmission system connected to the electricity grid of Bangladesh./अदानी समूह के इस ट्रांसनेशनल पावर प्रोजेक्ट से बांग्लादेश को 1496 मेगावाट बिजली की आपूर्ति होगी। यह बिजली बांग्लादेश के बिजली ग्रिड से जुड़ी 400 केवी समर्पित ट्रांसमिशन प्रणाली के माध्यम से आपूर्ति की जाएगी
- The commissioning of this project symbolizes the close cooperation and strong economic relations between the Adani Group and Bangladesh Power Development Board (BPDB). Adani Power has become a partner in the economic growth and prosperity of Bangladesh by supplying uninterrupted and reliable power at competitive tariffs./इस परियोजना का कमीशन होना अदानी समूह और बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड (बीपीडीबी) के बीच घनिष्ठ सहयोग और मजबूत आर्थिक संबंधों का प्रतीक है। अदानी पावर ने प्रतिस्पर्धी टैरिफ पर निर्बाध और विश्वसनीय बिजली की आपूर्ति करके बांग्लादेश के आर्थिक विकास और समृद्धि में भागीदार बन गया है।

6. For how many years has Atal Groundwater Scheme been extended after the end of its original year?/अटल भूजल योजना अपनी मूलवर्ष की समाप्ति के बाद कितने वर्ष बढ़ाया गया है?

- a) 1

## GENERAL KNOWLEDGE – THE 15MIN SHOW

### योजनाएँ खबरों में (Schemes in News)

- b) 2
- c) 3
- d) 4

### Atal Bhujal Water Scheme/अटल भूजल योजना

- To begin with, the Atal Ground Water Scheme will be implemented in seven states (Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh) over a five-year period (from 2020-21 to 2024-25). The scheme is expected to benefit approximately 8,350 gram panchayats in 78 districts across the country./शुरुआत करने के लिए, अटल भूजल योजना को सात राज्यों (गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश) में पांच साल की अवधि (2020-21 से 2024-25 तक) में लागू किया जाएगा। इस योजना से देश भर के 78 जिलों में लगभग 8,350 ग्राम पंचायतों को लाभ होने का अनुमान है।
- Decision to extend this Central Sector Water Conservation Scheme for additional two years (up to 2027) from its original expiry date of 2025. (May, 2023)/केंद्रीय क्षेत्र की इस जल संरक्षण योजना को अपनी मूल वर्ष 2025 की समाप्ति तिथि से अतिरिक्त दो वर्षों तक (वर्ष 2027 तक) बढ़ाने का निर्णय। (मई, 2023)
- The main objective of the scheme, implemented by the Ministry of Jal Shakti, is to improve the management of groundwater resources in selected water stressed areas in 7 states – Gujarat, Haryana, Karnataka, Madhya Pradesh, Maharashtra, Rajasthan and Uttar Pradesh./जल शक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित इस योजना का प्रमुख उद्देश्य 7 राज्यों - गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में चुनिंदा जल संकट क्षेत्रों में भूजल संसाधनों के प्रबंधन में सुधार करना है।

7. Obra 'D' thermal project is a project of which state?/ओबरा 'डी' तापीय परियोजना किस राज्य की परियोजना है?

- a) Madhya Pradesh/मध्य प्रदेश
- b) Uttar Pradesh/उत्तर प्रदेश
- c) Rajasthan/राजस्थान
- d) Gujarat/गुजरात

### Obra 'D' Thermal Project/ओबरा 'डी' तापीय परियोजना

- The proposal for establishment of this project of 2 x 800 MW (1600 MW) and project cost of Rs 17985.27 crore was approved by the Uttar Pradesh Government/उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2 x 800 मेगावाट (1600 मेगावाट) की इस परियोजना की स्थापना एवं परियोजना लागत 17985.27 करोड़ रुपये का प्रस्ताव स्वीकृत। (11 जुलाई, 2023)
- This project will be established by NTPC and Uttar Pradesh./इस परियोजना की स्थापना एनटीपीसी और उत्तर प्रदेश

## **GENERAL KNOWLEDGE – THE 15MIN SHOW**

### **योजनाएँ खबरों में (Schemes in News)**

- This will be done by Meja Urja Nigam Private Limited, a joint venture with 50:50 shareholding of State Electricity Generation Corporation Limited./राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड के 50:50 अंशधारिता के संयुक्त उद्यम मेजा ऊर्जा निगम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा की जाएगी।
- 7 This will be the first ultrasuper critical unit of the state./7 यह प्रदेश की पहली अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल यूनिट होगी।

8. 'Mera Gaon Meri Dharohar Project is a part of which project?'/मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना किस परियोजना का हिस्सा है?

- a) Pradhan Mantri Pranam Yojana/प्रधानमंत्री प्रणाम योजना
- b) Independence Cultural Festival/आजादी का सांस्कृतिक महोत्सव
- c) Azadi Ka Amrit Mahotsav /आजादी का अमृत महोत्सव
- d) Pradhan Mantri Kaushal Yojana/प्रधानमंत्री कौशल योजना

### **'My Village My Heritage Project'/'मेरा गांव मेरी धरोहर परियोजना**

- Launch of this unique initiative as part of Azadi Ka Amrit Mahotsav by Union Minister Amit Shah (July 27, 2023)
- केंद्रीय मंत्री अमित शाह द्वारा आजादी का अमृत महोत्सव के हिस्से के रूप में इस अनूठी पहल का शुभारंभ (27 जुलाई, 2023)
- This project has been launched by the Ministry of Culture in coordination with Indira Gandhi National Center for the Arts (IGNCA) under the National Cultural Mapping Mission. India's first international power project announced by Adani Group to start this project in Godda, Jharkhand to start supplying power to the power grid of Bangladesh. (July 15, 2023)
- संस्कृति मंत्रालय द्वारा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) के समन्वय से राष्ट्रीय सांस्कृतिक मानचित्रण मिशन के अंतर्गत यह परियोजना शुरू की गई है। भारत की पहली अंतरराष्ट्रीय बिजली परियोजना अडानी समूह द्वारा बांग्लादेश के बिजली ग्रिड को बिजली की आपूर्ति शुरू करने हेतु झारखण्ड के गोड्डा में इस परियोजना को शुरू करने की घोषणा। (15 जुलाई, 2023)

9. Space Science and Technology Awareness Training (START) program has been started by which organization?/Space Science and Technology Awareness Training (START) कार्यक्रम की शुरुआत किस संस्था के द्वारा किया गया है?

- a) ISRO
- b) Indian Institute of Science, Bangalore
- c) IIT Madras
- d) DRDO

### **Space Science and Technology Awareness Training (START) Program/अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी जागरूकता प्रशिक्षण (START) कार्यक्रम**

- Indian Space Research Organization (ISRO) launches this new entry level online training program for postgraduate and final year students of Physics and Technology./भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन

## GENERAL KNOWLEDGE – THE 15MIN SHOW

### योजनाएँ खबरों में (Schemes in News)

(इसरो) द्वारा भौतिक विज्ञान और प्रौद्योगिकी के स्नातकोत्तर और अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए इस नए प्रारंभिक स्तर के ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम की शुरुआत। (2 मई, 2023)

Full form of START - Space Science and Technology Awareness Training.

START का पूर्ण रूप - Space Science and Technology Awareness Training.

10. PM Pranam Yojana is a scheme related to which subject?/पीएम प्रणाम योजना किस विषय से संबंधित योजना है?

- a) Improving soil fertility and restoring soil nutrition/धरती की उपजाऊ क्षमता को बेहतर करना और मिट्टी में पोषण को फिर से स्थापित करना
- b) Groundwater conservation/भूजल संरक्षण
- c) Consolidation/चकबंदी
- d) All three above/उपरोक्त तीनों

### PM Pranam Yojana/पीएम प्रणाम योजना

- Approval of this scheme by the Cabinet Committee on Economic Affairs (June, 2023)आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा इस योजना को मंजूरी (जून, 2023)
- PM-Pranam stands for "Prime Minister's Program for Restoration, Awareness, Nurturing and Improvement of Fertility of Mother Earth"./पीएम- प्रणाम का तात्पर्य " Prime Minister's Program for Restoration, Awareness, Nurturing and Improvement of Fertility of Mother Earth" है।
- M PRANAM means Promotion of Alternative Nutrients for Agriculture Management Yojana. This is a master program whose objective is to improve the fertility of the earth and restore nutrition in the soil.
- M PRANAM का मतलब है प्रमोशन ऑफ अल्टरनेटिव न्यूट्रिएंट्स फॉर एग्रीकल्चर मैनेजमेंट योजना (Promotion of Alternate Nutrients for Agriculture Management Yojana) है. यह एक मास्टर प्रोग्राम है जिसका मकसद धरती की उपजाऊ क्षमता को बेहतर करना और मिट्टी में पोषण को फिर से स्थापित करना है.

11. The Ministry of Education in India has been celebrating Literacy Week since 2010 to promote awareness about the ULAS-Nav Bharat literacy programme./भारत में शिक्षा मंत्रालय उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए कब से तक साक्षरता सप्ताह मना रहा है।

- a) 1 से 8 अगस्त
- b) 1 से 8 सितम्बर
- c) 11 से 18 सितम्बर
- d) 21 से 28 सितम्बर

## **GENERAL KNOWLEDGE – THE 15MIN SHOW**

### **योजनाएँ खबरों में (Schemes in News)**

- The Ministry of Education in India is celebrating Literacy Week from September 1 to 8, 2023, to promote awareness about the ULAS-Nav Bharat literacy programme./भारत में शिक्षा मंत्रालय उल्लास-नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए 1 से 8 सितंबर, 2023 तक साक्षरता सप्ताह मना रहा है।
- Literacy Week aims to encourage large-scale participation and inculcate a sense of responsibility among all citizens to achieve complete literacy in India./साक्षरता सप्ताह का लक्ष्य भारत में पूर्ण साक्षरता प्राप्त करने के लिए बड़े पैमाने पर भागीदारी को प्रोत्साहित करना और सभी नागरिकों के बीच जिम्मेदारी की भावना को जागरूक करना है।
- Various stakeholders including students, teachers, volunteers, government employees and citizens will participate in the campaign./अभियान में छात्रों, शिक्षकों, स्वयंसेवकों, सरकारी कर्मचारियों और नागरिकों सहित विभिन्न हितधारक भाग लेंगे।
- ULAS- Nav Bharat Literacy Program is a centrally sponsored scheme in line with the National Education Policy (NEP) 2020, which will run from 2022 to 2027./उल्लास- नव भारत साक्षरता कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी) 2020 के अनुरूप एक केंद्र प्रायोजित योजना है, जो 2022 से 2027 तक चलेगी।

12. Which state has launched 'Sashakt Mahila Loan Scheme'?/'सशक्त महिला ऋण योजना' की

शुरुआत किस राज्य ने की है?

- a) Rajasthan/राजस्थान
- b) Himachal Pradesh/हिमाचल प्रदेश
- c) Uttar Pradesh/उत्तर प्रदेश
- d) Uttarakhand/उत्तराखंड

- sashakt Mahila Loan Scheme is an initiative of Himachal Pradesh State Cooperative Bank (HPSCB) to provide loans to women to pursue their entrepreneurial dreams, engage in livelihood activities, meet their day-to-day needs and uplift their families./
- सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी बैंक (एचपीएससीबी) की एक पहल है जो महिलाओं को उनके उद्यमशीलता के सपनों को आगे बढ़ाने, आजीविका गतिविधियों में संलग्न होने, उनकी दिन-प्रतिदिन की जरूरतों को पूरा करने और उनके परिवारों के उत्थान के लिए ऋण प्रदान करेगी।

13. 'Mission Vatsalya' scheme launched recently is related to which subject?/हाल ही में द्वारा जारी योजना मिशन वात्सल्य' योजना किस विषय से सम्बंधित है?

- a) Girls education/बालिका शिक्षा
- b) To ensure institutional and financial support for pregnant minor victims/गर्भवती नाबालिग पीड़ितों के लिए संस्थागत और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना
- c) Girl employment/बालिका रोजगार

## GENERAL KNOWLEDGE – THE 15MIN SHOW

### योजनाएँ खबरों में (Schemes in News)

d) To help orphan girls/अनाथ बालिकाओं की सहायता हेतु

#### मिशन वात्सल्य योजना

- The Central Government has launched a new relief scheme under the 'Mission Vatsalya' scheme in relation to the abandonment of minor girls who are victims of rape by their families when they become pregnant./केंद्र सरकार ने दुष्कर्म पीड़ित नाबालिग लड़कियों के गर्भवती होने पर परिवारों द्वारा उनका परित्याग करने के संबंध में 'मिशन वात्सल्य' योजना के अंतर्गत एक नई रहत योजना आरंभ की है।
- According to Women and Child Development Minister Smriti Irani, the new scheme launched under the aegis of 'Nirbhaya Yojana' aims to ensure institutional and financial support for pregnant minor victims who have no means to take care of themselves./महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के अनुसार, 'निर्भया योजना' के तत्वावधान में आरंभ की गई नयी योजना का उद्देश्य उन गर्भवती नाबालिग पीड़ितों के लिए संस्थागत और वित्तीय सहायता सुनिश्चित करना है, जिनके पास खुद की देखभाल करने का कोई साधन नहीं है।

14. What is the main objective of Amrit Dharohar Yojana?/अमृत धरोहर योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है?

a) Protecting world heritage/विश्व विरासत धरोहर की रक्षा करना

**b) Encouraging optimal use of wetlands/आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करना**

c) Reconstruction of intangible heritage/अमूर्त धरोहरों का पुनर्निर्माण

d) Protecting cultural heritage/संस्कृतिक धरोहर की रक्षा करना

- On the occasion of World Environment Day (June 5), PM Narendra Modi launched two schemes - Amrit Dharohar and MISHTI (Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Income) aimed at reviving the country's wetlands and mangroves./विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून) के अवसर पर, पीएम नरेंद्र मोदी ने देश की आर्द्रभूमि और मैंग्रोव को पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से दो योजनाओं - अमृत धरोहर और मिष्ठी (मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटाट्स एंड टैजिबल इनकम) की शुरुआत की।

#### Amrit Dharohar Yojana/अमृत धरोहर योजना

- The scheme was first announced by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Union Budget 2023-24./इस योजना की घोषणा पहली बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के केंद्रीय बजट में की थी।
- The plan will be implemented over the next three years to encourage optimal use of wetlands and promote biodiversity, carbon stocks, ecotourism opportunities and income generation for local communities./आर्द्रभूमि के इष्टतम उपयोग को प्रोत्साहित करने और स्थानीय समुदायों के लिए जैव विविधता, कार्बन स्टॉक, इकोटूरिज्म के अवसरों और आय सृजन को बढ़ावा देने के लिए योजना को अगले तीन वर्षों में लागू किया जाएगा।



## **GENERAL KNOWLEDGE – THE 15MIN SHOW**

### **योजनाएँ खबरों में (Schemes in News)**

#### **MISHTI (Mangrove Initiative for Shoreline Habitats and Tangible Income)/मिष्टी (मैंग्रोव इनिशिएटिव फॉर शोरलाइन हैबिटेट्स एंड टैजिबल इनकम)**

- The scheme was first announced by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman in the Union Budget 2023-24./इस योजना की घोषणा पहली बार केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2023-24 के केंद्रीय बजट में की थी।
- It will facilitate mangrove plantation on salt-rich lands along the sea coast of India./यह भारत के समुद्री तट के साथ लवण युक्त भूमि पर मैंग्रोव वृक्षारोपण की सुविधा प्रदान करेगा।
- The PM said that in the last nine years the number of wetlands and Ramsar sites in India has increased almost three times than before./पीएम ने कहा कि पिछले नौ वर्षों में भारत में आर्द्रभूमि और रामसर स्थलों की संख्या पहले की तुलना में लगभग तीन गुना बढ़ गई है।
- India currently has 75 Ramsar sites which are wetlands of international importance and have been designated under the criteria of the Ramsar Convention on Wetlands./भारत में वर्तमान में 75 रामसर स्थल हैं जो अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि हैं और आर्द्रभूमि पर रामसर सम्मेलन के मानदंडों के तहत नामित किए गए हैं।
- India also has about 3% of South Asia's mangrove population./भारत में दक्षिण एशिया की मैंग्रोव आबादी का लगभग 3% हिस्सा भी है।

15. The foundation stone for redevelopment of how many railway stations across India will be laid under 'Amrit Bharat Station Scheme'?/अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत भारत भर में कितने रेलवे स्टेशनों के पुनर्विकास की आधारशिला रखी जाएगी?

- a) 500
- b) 508**
- c) 518
- d) 550

- अमृत भारत स्कीम के तहत 508 रेलवे स्टेशनों में से उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सबसे ज्यादा रेलवे स्टेशनों का कार्याकल्प किया जाएगा. इसमें से पत्येक में 55 स्टेशनों का कार्याकल्प किया जाएगा.
- वहीं बिहार के 49 स्टेशनों का कार्याकल्प होगा, महाराष्ट्र के 44, पश्चिम बंगाल के 37 स्टेशनों का कार्याकल्प किया जाएगा.
- इसके अलावा मध्य प्रदेश, असम, ओडिशा, पंजाब, गुजरात, तेलंगाना, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा और कर्नाटक राज्यों के रेलवे स्टेशनों की भी तस्वीर बदली जाएगी.
- Under the Amrit Bharat Scheme, out of 508 railway stations, maximum railway stations in Uttar Pradesh and Rajasthan will be revamped. In each of these, 55 stations will be rejuvenated.
- Whereas 49 stations in Bihar will be transformed, 44 stations in Maharashtra and 37 stations in West Bengal will be transformed.

## **GENERAL KNOWLEDGE – THE 15MIN SHOW**

### **योजनाएँ खबरों में (Schemes in News)**

- Apart from this, the picture of railway stations in the states of Madhya Pradesh, Assam, Odisha, Punjab, Gujarat, Telangana, Jharkhand, Andhra Pradesh, Tamil Nadu, Haryana and Karnataka will also be changed.

Others:

### **Uttar Pradesh Matribhoomi Yojana/उत्तर प्रदेश मातृभूमि योजना**

The scheme was launched by Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath at Indira Gandhi Pratisthan, Lucknow. (June 2, 2023)/उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान, लखनऊ में इस योजना का शुभारंभ। (2 जून, 2023)

Under this scheme, all the natives of Uttar Pradesh who are currently living anywhere in the country or the world and are capable and willing to develop their village or area. Can become participants./इस योजनांतर्गत उत्तर प्रदेश के सभी मूल निवासी जो मौजूदा समय में देश या विश्व में कहीं भी रह रहे हैं और अपने गांव या क्षेत्र का विकास करने में सक्षम तथा इच्छुक हों. सहभागी बन सकते हैं।

### **Nand Baba Milk Mission Scheme/नंद बाबा दुग्ध मिशन योजना**

This scheme has been launched by the Government of Uttar Pradesh to provide facility to milk producers to sell their milk at fair prices in villages through dairy cooperative societies. (June 6, 2023)

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा दुग्ध उत्पादों को डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से गांवों में उचित मूल्य पर अपना दूध बेचने की सुविधा प्रदान करने हेतु इस योजना की शुरुआत। (6 जून, 2023)

### **Transforming Lives, Building Futures: Skill Development and Entrepreneurship in North-East/ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स, बिल्डिंग फ्यूचर्स : स्किल डेवलपमेंट एण्ड एंटरप्रेन्योरशिप इन नॉर्थ-ईस्ट**

Union Minister Dharmendra Pradhan, G. Launch of this special skill initiative by Kishan Reddy and Rajeev Chandrasekhar in New Delhi to create a strong skill centric and industry ready ecosystem in the North-Eastern region. (August 8, 2023)

केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, जी. किशन रेड्डी और राजीव चंद्रशेखर द्वारा नई दिल्ली में उत्तर-पूर्वी क्षेत्र में एक मजबूत कौशल केंद्रित और उद्योग के लिए तैयार पारिस्थितिकी तंत्र बनाने हेतु इस विशेष कौशल पहल की शुरुआत। ( 8 अगस्त, 2023)

### **AI for India 2.0/एआई फॉर इण्डिया 2.0**

This free online training program was launched by Union Minister Dharmendra Pradhan on the occasion of World Youth Skills Day./केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान द्वारा विश्व युवा कौशल दिवस के अवसर पर इस निःशुल्क ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ। (15 जुलाई, 2023)

### **Carbon Credit Trading Plan, 2023/कार्बन क्रेडिट व्यापार योजना, 2023**

Notified by the Union Ministry of Power (June 28, 2023)

- Under the scheme, the Central Government will constitute a National Steering Committee for the Indian Carbon Market./केंद्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा अधिसूचित (28 जून, 2023) / इस योजना के तहत, केंद्र सरकार भारतीय कार्बन बाजार के लिए राष्ट्रीय संचालन समिति का गठन करेगी।

## **GENERAL KNOWLEDGE – THE 15MIN SHOW**

### **योजनाएँ खबरों में (Schemes in News)**

- **Gabon's first agriculture/गैबॉन की पहली कृषि** -SEZ project Union Minister Dharmendra Pradhan flagged off the scheme from New Delhi. /एसईजेड परियोजना केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली से इस योजना को हरी झण्डी दिखाकर रवाना किया। (14 जून, 2023)
- **Rooftop Solar Photovoltaic Project at IIT Jodhpur/आईआईटी जोधपुर में रूफटॉप सौर फोटोवोल्टिक परियोजना:** Launch of this first project by NTPC Vidyut Vyapar Nigam Limited (NVVN). /एनटीपीसी विद्युत व्यापार निगम लिमिटेड (एनवीवीएन) द्वारा अपनी इस पहली परियोजना की शुरुआत। (14 जून, 2023)
- **World Bank's first road safety project in South Asia/विश्व बैंक की दक्षिण एशिया में पहली सड़क सुरक्षा परियोजना:** The project was launched by the World Bank in Bangladesh with a financing agreement of US\$358 million. (June 14, 2023)/विश्व बैंक द्वारा बांग्लादेश में 358 मिलियन अमेरिकी डॉलर के वित्तपोषण समझौते के साथ इस परियोजना की शुरुआत। (14 जून, 2023)

### **Integrated Food Security Scheme/एकीकृत खाद्य सुरक्षा योजना**

- The scheme, launched from January 1, 2023, was named Pradhan Mantri Garib Kalyan Anna Yojana (PMGKAY)./1 जनवरी, 2023 से शुरू की गई इस योजना का नाम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) रखा गया। (जनवरी, 2023)
- उद्देश्य - To provide free food grains under the National Food Security Act to more than 80 crore poor and extremely poor people./80 करोड़ से अधिक गरीब और अत्यंत निर्धन लोगों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत निःशुल्क खाद्यान्न उपलब्ध कराना।

### **Sunni Dam Hydroelectric Project/सुन्नी बांध जलविद्युत परियोजना**

- Cabinet Committee on Economic Affairs has approved the investment for this 382 MW hydropower project to be implemented by SJVN Limited in Himachal Pradesh./आर्थिक मामलों की मंत्रिमण्डलीय समिति द्वारा हिमाचल प्रदेश में एसजेवीएन लिमिटेड द्वारा क्रियान्वित की जाने वाली 382 मेगावॉट की इस जलविद्युत परियोजना के लिए निवेश को स्वीकृति। (4 जनवरी, 2023)

### **अबाधा (ABADHA) योजना**

- Odisha Cabinet approves increase of Rs 1000 crore in the total cost outlay of this scheme (June 21, 2023) The full form of SABADHA is "Augmentation of Basic Amenities and Development of Heritage and Architecture"./ओडिशा मंत्रिमण्डल द्वारा इस योजना के कुल लागत परिव्यय में 1000 करोड़ रुपये की वृद्धि को मंजूरी (21 जून, 2023) SABADHA का पूर्ण रूप " Augmentation of Basic Amenities and Development of Heritage and Architecture" है।